ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

राष्ट्रहित के अनुसार भारत की बदलती विदेश नीति

India's Changing Foreign Policy According To National Interest

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

सत्येन्द्र कुमार
शोध छात्र,
विश्वविद्यालय राजनिति विज्ञान विभाग,
बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर,
बिहार, भारत

सारांश

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात् यानि 1945 ई0 से विश्व एक नए दौर में प्रवेश किया, जिसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। जिसने दुनिया को खेमों में बॉट दिया। एक का नेतृत्वकर्त्ता अमेरिका एवं दुसरे का नेतृत्वकर्त्ता सोवियत संघ रूस था। ऐसी स्थिति में औपनिवेश से मुक्त हुए नवोदित राष्ट्रों को अपने स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण की उपाए सूझी। इस समय भारत भी औपनिवेशिक राज्य से स्वतंत्र होकर नवोदित राज्य बन चुका था। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू, कर्नल नसीर एवं मार्शल टीटो की जुगलबंदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरूआत की और इसमें नवोदित राष्ट्रों को जोड़ने का प्रयास किया। भारत की स्वतंत्रा और 1990 के दशक के मध्य भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रहित को साधते हुए आगे बढता रहा। इस दरम्यान भारत को अमेरिकी गुट में शामिल नहीं होने के कारण कई मौके पर अमेरिका की नाराजगी भी झेलनी पड़ी और संबंध अच्छे नहीं रहे। वहीं दूसरी तरह सोवियत संघ के साथ भारत की रिश्ते अच्छे रहे एवं सकंट के समय हमेशा भारतीय विदेश नीति को सुरक्षा मिली। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व राजनीति बदल गई। दो धुव्रीय विश्व में अमेरिकी नेतृत्व वाली एक धुव्रीय विश्व बन गया। भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भारत को उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने को मजबूर कर दिया एवं गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत किनारा करता चला गया। 1998 में परमाणु परीक्षण ने भारतीय विदेश नीति को मजबूती प्रदान किया। वहीं 2006 ई0 के पश्चात् भारतीय विदेश नीति से नफरत करने वाले राज्य धीरे–धीरे भारत के करीब आने लगे जिसमें अमेरिका और चीन मुख्य रूप से भारत से मेल–जोल बढ़ाने लगे। जिससे चीन और अमेरिका भारत की सबसे बड़े आर्थिक साझेदार बन गए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति और अधिक सशक्त दिखाई दे रही है, जिसमें अमेरिका के प्रति भारत का झुकाव बढ़ा है और रूस के साथ भी मेल–जोल बरकरार है, लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध उतार–चढ़ाव के दौर से गुजर रहें है।

After the end of World War II, ie from 1945 AD, the world entered a new phase, which is called the era of Cold War. Who divided the world into camps. One was led by the US and the other led by the Soviet Union was Russia. In such a situation, the newly liberated nations, who were liberated from colonialism, were thought to have decided their independent foreign policy. At this time India too had become a budding state independent of the colonial state. Jugalbandi of Pandit Jawaharlal Nehru, Colonel Naseer and Marshal Tito initiated the Non-Aligned Movement and tried to connect the budding nations with it to determine their independent foreign policy. India's independence and India's foreign policy continued to move forward, serving its national interest during the mid-1990s. In the meantime, due to India not joining the American bloc, on many occasions, the US has also suffered resentment and relations were not good. On the other hand, India's relations with the Soviet Union were good and Indian foreign policy always got security at the time of the session. After the dissolution of the Soviet Union in 1991, world politics changed. The two-polar world became an American-led polar world. The weak economic condition of India forced India to adopt the policy of liberalization, privatization and globalization and moved away from the policy of non-alignment. The nuclear test in 1998 strengthened Indian foreign policy. At the same time, after 2006, states that hated Indian foreign policy gradually started coming closer to India, in which America and China started to interact mainly with India. With this, China and America became India's largest economic partners. India's foreign policy appears to be more powerful during the tenure of Prime Minister Modi, in which India's inclination towards America has increased and interaction with Russia remains intact, but India's relations with China have been fluctuating. Passing by.

मुख्य शब्द : विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, स्वतंत्र विश्व राजनति, महाशक्ति।

प्रस्तावना

विदेश नीति एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से राष्ट्रहित को साधा जाता है, जिसमें नीतियों, कूटनीतियों की ऐसी चाले होती हैं जो हर स्थिति में राष्ट्रहित में होती है। जहॉ तक भारतीय विदेश नीति की बात की जाती है तो इसके भी अपने नीतियॉ एवं सिद्धांत है। इनके विदेश नीति पर गौर करें तो पता चलता है कि स्वतंत्रा के पूर्व भी औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद की नीति का विरोधी और स्वतंत्रा एवं अंर्तराष्ट्रीय सद्भावना का प्रबल सर्मथक रहा साथ ही स्वतंत्रा के पश्चात् भी पूर्व की नीतियों का अनुसरण करते हुए नए सिद्धांतो अर्थात पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीतियों को आत्मसात करते हुए अपने विदेश नीतियों को परिष्कृत करने का प्रयास जारी रखा। पंडित जवाहर लाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार माना जाता है। उनका मानना था कि दुनिया दो सैन्य गुटों में विभाजित है जो शक्ति संतुलन पर आधारित है। इसके अलावा विभिन्न विरोधी विचारधाराओं पर आधारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में एक विश्व की कामना करते हुए विश्व संघर्षों, घृणाओं एवं आतंरिक द्वद्वो के बाद अंततः निश्चित रूप से घनिष्ठ सहयोग व विश्व राष्ट्रकुल की ओर अग्रसर होगा।[1]

भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता एक लंबे समय तक राष्ट्रहित की प्रतिपूर्ति का साधन बना रहा। इसके कई पहलू रहें, परंतु सामान्य रूप से इसे शीतयुद्ध व उससे संबद्ध गुटबंदियों से अलग रहने की नीति माना गया। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकतें है कि शीतयुद्ध से संबद्ध सैन्य गठबंधनों में भागीदारी न करना। इसके अतिरिक्त, इसे भारत द्वारा अंर्तराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने वाला सिद्धांत भी माना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा भारत अपने विकल्पों की स्वतंत्रा के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तथा मुद्दों के योग्यता के आधार सर्मथन करता रहा है।[2] पंडित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि हमारे देश का संबंध पड़ोसियों के साथ अच्छे होना चाहिए इसके लिए उन्होंने पंचशील जैसे नीतियों का अनुसरण किया। यह नीति नैतिकता व शांति स्थापना के मुल्यों से ओत–प्रोत था। जिसे गुटनिरपेक्ष नीति का ही एक भाग माना गया। पंडित नेहरू अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को केवल कल्पना तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे बल्कि विश्व शांति हेतु उसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 के भारत–चीन व्यवपारिक समझौते की प्रस्तवाना में प्रतिपादित किया गया, जिसे बाद में 28 जून 1954 को चीन की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोहराया गया। [3]

इस सिद्धांत के तहत् पॉच प्रमुख बातों की जिक्र की गई–

1. एक–दुसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान
2. पारस्परिक आक्रमण न करना
3. एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
4. समानता और पारस्परिक लाभ एवं
5. शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व।

यह सिद्धांत केवल भारत–चीन संबंधों तक ही नहीं सीमित था बल्कि यह भारत की सभी पडोसी राष्ट्रों तथा विश्व के राष्ट्रो के मध्य संबंध निर्धारण हेतु उपयोगी सिद्धांत था।[4] लेकिन यह सिद्धांत उस समय निर्मुल साबित हुआ जब भारत के निकटतक पड़ोसी देश चीन ने अपनी प्रसारवादी नीतियों का अवलंबन करते हुए अक्टुबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया और ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' का नारा कपोल कल्पना साबित हुआ। भारतीय विदेश नीति स्तब्द्ध थी जिसे जोर का झटका लगा था इसके क्रिया–कलापों पर प्रश्नचिन्ह लग चुका था जिसे स्वपनों की दुनिया से यथार्थ की दुनिया में लाकर पटक दिया था और यह सीख देकर चला गया कि विदेश नीतियों को तीक्ष्ण और चौकन्नी होनी चाहिए। भारत विदेश नीतियों के मोर्चे पर इस समय लड़खड़ातें हुए हर संभव प्रयास करते हुए अमेरिकी मदद मांगते हुए राष्ट्रहित को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

यू ंतो भारतीय विदेश नीति की सराहना तो वैश्विक स्तर पर होती रही है जिसने नवोदित राष्ट्रो को गुटनिरपेक्ष जैसा मंच प्रदान किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। 1965 में भारत–पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारत की विजय ने भारतीय विदेश नीति की प्रतिष्ठा को बढ़ाया साथ ही 1971 में भी भारत–पाकिस्तान युद्ध के समय अपने राष्ट्रहितों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानतें हुए भारत ने पूर्व सोवियत संघ रूस के साथ भारत–सोवियत मैत्री संधि को अंतिम रूप देते हुए राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा प्रदान की। यह उस समय हुई थी जब अमेरिका पाकिस्तान के सर्मथन में खुलकर सामने आ चुका था। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस संधि को भारत के द्वारा अपनायी गई गुटनिरपेक्षता की नीति के विरूद्ध बताया था और यह तर्क देने का प्रयास किया कि यह तो भारत–सोवियत के बीच सुरक्षात्मक संधि है लेकिन भारत ने कहा कि हमारे गुटनिरपेक्षता की नीति कायम है और यह संधि हमारी राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है।

1990 का दशक भारतीय विदेश नीति के बदलाव का महत्वपूर्ण दशक माना जाता है इस समय सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। अब दुनिया दो धुव्रीय न रहकर अमेरिकी नेतृत्व वाली एक धुव्रीय व्यवस्था बन गयी। विभिन्न देशों के विदेश नीति में तीव्र गति से बदलाव होना प्रारंभ हो गया जिसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर भी पड़ा और भारत ने अपनी आर्थिक मजबूती, विकास एवं विश्व के देशो के साथ बेहतर कनेक्टविटी के लिए उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनातें हुए अपना द्वार विश्व के अन्य देशों के लिए खोल दिया। गुटनिरपेक्षता की खट्टे–मीठे अनुभवों ने इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया। विद्वानों का मानना था कि जब दुनिया एक धुव्रीय हो गया तो फिर गुटनिरपेक्षता की क्या जरूरत। लेकिन इसके प्रासंगिकता के पक्षकारों का मानना था कि भले ही दुनिया एक धुव्रीय हो गया हो पर भारत स्वतत्र विदेश नीति का अवलंबन करता रहेगा क्योंकि विश्व में बहुत सारी ऐसी

उभरती हुई समस्याएँ जो गुटनिरपेक्षता को बनाए रखने पर बल देता है। जुन 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने गुटनिरपेक्षता का बचाव करने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि ''पहले की तुलना में गुटनिरपेक्षता की नीति का औचित्य आज और महत्वपूर्ण है। जब तक राष्ट्रों की दादागिरी चलती रहेगी तब तक भारत इस नीति को अपनाए रहेगा।'' इसके बाद इन्द्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री बने और जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी नेहरू जी रास्ते पर चलते हुए अंर्तराष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्षता की नीति की सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने 1997 मे संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए कहा ''औपनिवेशिक एवं असक्त राष्ट्रो की आवाज की अभिव्यक्ति थी, राजनीति और आर्थिक रूप से असमान विश्व का यर्थाथ चित्रण एवं उसकी कार्यसूची थी। यह अपने वाले समय के लिए विवेक की आवाज एवं सकारत्मक कार्य योजना है जिसकी यह मांग है कि सभी तरफ प्रमुख विषयों पर विश्वव्यापी समस्याओं पर साझा उद्देश्य और योगदान किया जाए''।[5] इन्द्र कुमार गुजराल ने भारतीय विदेश नीति को धार देते हुए गुजराल सिद्धांत के रूप में पडोसी देशों से संबंध मजबुत करने की वकालत की, साथ ही यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे और सौहादपूर्ण संबंधों की प्राथमिकता देगा। इसके अलावे इजरायल, अरब देशों, ब्रिटेन, एवं रूस के साथ भी संबंध मधुर रहेंगें। दूसरी तरफ भारत आर्थिक और व्यवपारिक हितों को आशियान एवं दक्षिण पूर्व एशिया से भी जोड़ने की रही है। इस दौरान भारत परमाणु अप्रसार सी0टी0बी0टी0 तथा अर्तराष्ट्रीय आतंकवाद पर आम सहमति प्राप्त करने में काफी सफलता प्राप्त की है।[6]

जब भारत द्वारा 1998 परमाणु परीक्षण किया गया तब पूरी दुनिया में खलबली मच गयी और भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित हुआ, इस परीक्षण की बहुत सारे देशो ने आलोचनाएँ भी की और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन कुछ वर्षो के पश्चात् दुनिया के महाशक्तियों का भारत के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। अमेरिका द्वारा 2006 में परमाणु संधि 123 किया गया , चीन के साथ व्यवपार के लिए 64 वर्षो के बाद सिक्मिम में नाथुला पास मार्ग खोल दिया गया। अन्य देशों के साथ विदेशी निवेश के अवसर प्रदान किये और प्राप्त भी किये गए। भारत वैश्विक आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर खुलकर सामने आया एवं विभिन्न अर्तराष्ट्रीय संगठनों जो मूलतः आर्थिक विकास के लिए स्थापित किये गए, जैसे जी–20, ब्रिक्स, बिम्सटेक, शंघाई सहायोग संघटन आदि में सहभागिता बढ़ाते हुए अपनी विदेश नीति को मजबूत किया।

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद विदेश नीति के मोर्चे पर प्रगति देखी जा रही है। इस काल की विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति मानी जा रही है। 'पड़ोसी पहले' की नीति हो या फिर 'लूक इस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट इस्ट पॉलिसी' में परिवर्तन करने की हो या फिर अमेरिका जापान के साथ लॉजिस्टिक सहयोग एवं समझौता हो या फिर दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया के साथ दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती गतिविधियां एवं चीन की 'स्ट्रीग ऑफ पर्ल्स' का जवाब 'स्ट्रीग आफ डायमंड' के साथ देना हो ये सब बदलती विदेश नीति का परिचायक है। भारत चीन के बीच उत्पन्न तनाव के बीच भारत अमेरिका के संबंधों पर जुलाई 2020 को भारत के विदेश मंत्री एस0 जयशंकर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुटनिरपेक्षता भले ही पुराना सिद्धांत हो चुका है लेकिन भारत कभी भी किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता टर्म एक खास युग और भू–राजनीति परिदृश्य को लेकर था। लेकिन इसका एक पहलू था स्वतंत्रा जो हमारे लिए आज भी अहमियत रखता है।[7]

अध्ययन का उद्देश्य

राष्ट्रहित के अनुसार भारत की विदेश नीति बदलती रही है और इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत की बदलती विदेश नीति का मुल्यांकन करना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त आलेखों से स्पष्ट है कि राष्ट्रहित के अनुसार भारत की बदलती विदेश नीति जो कभी औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद की नीति का पुरजोर विरोध करती थी लेकिन जब अर्तराष्ट्रीय परिदृश्य बदला और विश्व के लगभग सभी देश स्वतंत्र होने लगे, रंगभेद मिटने लगा तो भारत ने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए शीतयुद्ध कालीन राजनीति में किसी भी गुट से न मिलने की नीति का अनुसरण किया। और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी। लेकिन भारत के राष्ट्रहित पर जब–जब खतरा उत्पन्न हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ से मदद मॉगने में भी पीछे नहीं रहा। जैसे भारत चीन युद्ध 1962 के समय अमेरिका से मदद की मांग एवं भारत पाक युद्ध 1971 में सोवियत संघ से मदद लेने में पीछे नहीं रहा। 1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अपने द्वारा खोल दिये। 1998 में परमाणु परीक्षण से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आया। अब दशकों से भारत से नफरत करने वाले राज्य भारत के निकट आने लगे और आगे चलकर भारत के सबसे बड़े आर्थिक साझेदार बन गए। अमेरिका और जापान के साथ कई सुरक्षात्मक समझौते भी किया गए है, विभिन्न देशों के साथ युद्ध अभ्यास हो रहें हैं। भारत अब वेट एण्ड वॉच की स्थिति में न रहकर अब आक्रामक स्थिति में आ गया है। यह भारतीय विदेश नीति की सबसे बडी बदलावों में से एक है। भारत का वैश्विक स्तर पर विभिन्न अर्तराष्ट्रीय संगठनों में भी भागीदारी एवं वर्चस्व बढ़ा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *जवाहर लाल नेहरू, इंडिया एण्ड वर्ल्ड, लंदन 1936 पृ0 सं0 – 70*
2. *जवाहर लाल नेहरू, इंडिया एण्ड वर्ल्ड, लंदन 1936 पृ0 सं0 – 33*
3. *भारतीय संसद, पार्लियामेन्ट्री डिबेट्स (लोकसभा) भॉल्युम – VI अंक 70, 15 मार्च 1954 पृ0 सं0 – 7496*
4. *भारतीय संसद, पार्लियामेंट्री डिबेट्स (लोकसभा) भॉल्युम – VI अंक 70, 15 मार्च 1954 पृ0 सं0 – 67*
5. *दूरस्थ शिक्षा निदेशालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ''भारत की विदेश नीति''*
6. *उपरोक्त*
7. *aajtak.in, 24 july 2020*